

अजमेर
नम्बर व तारीख
पत्र जो इस
द्वारा जारी

14

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2022/225

चन्दन सिंह व/अपील प्राधिकारी

तारीख	2022/422	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील जारी हुए
पेशी	श्री रोहित शर्मा	श्री राजीव सिंह - 1	402

17
7
23

चन्दन सिंह बनाम भूपेन्द्रसिंह (2022/422)
पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांत एवं अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांत एवं अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 01 एवं राजकीय अभिभाषक को दिनांक 04.07.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 व 14 म्याद अधिनियम एवं अपील पर पर सुना गया।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 व 14 म्याद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं।

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांत ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र पर कथन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 06.05.2022 से व्यथित होकर अपीलांत ने माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व में अपील संख्या 134/2022 प्रस्तुत की, जिस पर माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 21.06.2022 को विचारण न्यायालय को 30 दिवस में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को तय करने के निर्देश जारी किये थे, किन्तु तहत् न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.202 तक तय नहीं कर मात्र तारीखें दी जारी है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2022 की पालना में अपीलांत ने तहत् विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. दिनांक 24.06.2022 को मय आदेश दिनांक 21.06.2022 पेश किया, जिसकी आगामी पेशी दिनांक 08.07.2022 को वादी वकील को अनापत्ति होने पर आवेदन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. स्वीकार कर लिया गया था। तत्पश्चात भी पत्रावली को दिनांक 02.09.2022 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. के जवाब हेतु नियत कर दिया। जिसके बाद मात्र पेशियों नियत की जा रही है। दिनांक 07.10.2022 को पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. पर बहस सुनकर वास्ते आदेश नियत कर दिया। जिसके बाद मात्र पेशियों की गई तथा दिनांक 18.11.2022 को पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. पर बहस सुनने हेतु नियत कर दिया और अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को तय नहीं का मात्र तारीखें प्रदान कर अविधिक आदेशों सृजित की जा रही है। रेस्पोजेन्ट संख्या 01 ने मात्र रेस्पोजेन्ट संख्या 02 के विरुद्ध वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर विचारण न्यायालय ने निहित क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग किया है। जिससे अपीलांत के हितो को प्रभावित किया है। अपीलांत का प्रकरण गुणावगुण पर मजबूत है जिसे मेरिट पर निर्णित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य नहीं किया गया तो अपीलांत को अपूरणीय क्षति कारित होगी। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का शमन किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें।

अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था तथा इसकी जानकारी प्रार्थी/अपीलांत को थी फिर भी प्रार्थना पत्र में जो देरी के कारण अंकित किये गये हैं जो मिथ्या एवं गलत है, इसलिए प्रार्थना पत्र 5 म्याद अधिनियम को खारिज किया जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांत द्वारा प्रार्थना पत्र में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं तथा विभिन्न माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने अनेको निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां तक हो सके अपील का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः न्यायहित में प्रार्थी/अपीलांत द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को अंदर भिदाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थीगण/अपीलांतस द्वारा प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

--- 01/11/23 ---

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

422/2022/215 RTA

तन्हा रिज 415 243/06

अज 3
2022/225

तारीख	2022/422	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व अहकाम अन्तर्गत हुकम की तारीख
पेशी	श्री रोहित सोनी	श्री अजीत सिंह 1 GA 2	20

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 व 14 म्याद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर भियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अपील का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। अभिभाषक अपीलांत ने दौरान बहस अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड सह-खातेदारान कुलदीन सिंह, रवीन्द्रसिंह पुत्रान अरुणसिंह एवं मंजू कंवर पत्नि अरुण सिंह के नाम 267/390 हिरसा सम्वत् 2073-76 जमाबंदी वर्ष 2019 में अंकित है, जिससे कि अपीलांत ने दिनांक 20.04.2022 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया है। उक्त आराजी पर विक्रेतागण पूर्वजों के समय से अपने-अपने हिरसे पर शांतिपूर्वक सह-खातेदार की हैसियत से काश्त कर रहे है, जिस क्रम में उन्होंने अपने अपने हिरसे अनुसार बाड़, फसल तारबंदी आदी की हुई है, चूंकि वादी व उसका परिवार अज्ञाति प्रिय व्यक्ति होकर झगडे फसाद कर हैरान-परेशान करने की नेईयत रखते है। जिस क्रम में रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने मात्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 के विरुद्ध वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत की हैं। वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं होने से उसके कब्जे में हस्तक्षेप का प्रश्न ही प्रकरण में विद्यमान नहीं है, जिससे कि अन्तरिम स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष देय योग्य नहीं है, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशित आदेश की आड़ में अपीलांत को उसके खातेदारी की आराजी बाबत हैरान-परेशान किया जा रहा है। जिसके बाद माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 21.06.2022 की पालना में अन्तरिम अस्थायी निषेधा को तय नहीं कर मात्र तारीखें प्रदान कर अविधिक आदेशिकाये सृजित की जा रही है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी रेकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। जैसा कि न्यायिक दृष्टांतो 2016 आर.बी.जे. पेज 244, 2004 आर.बी.जे. पेज 163, 2005 आर.बी.जे. पेज 87 में प्रतिपादित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में भी स्थगन आदेश रेकार्डेड खातेदार के विरुद्ध प्रदान किया गया है, जो कि अविधिक आदेश की श्रेणी में आता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांत स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 28/2020 बउनवानी भूपेन्द्र बनाम राज.सरकार में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी करावें।

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने दौरान जवाब/बहस अपील में कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह व उनके पिता नरदेव सिंह ने पूर्व खातेदार छीतर पुत्र रामचन्द्र दरोगा से उक्त भूमि कुल 08-00-10 बीघा में से 05-09-10 बीघा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था इस खसरे की शेष भूमि 02-11-00 अन्य व्यक्ति ने खरीदी थी जैसा की नामान्तकरण संख्या 127 दिनांक 13.09.1988 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 व उसके पिता के नाम उक्त क्रय शुदा भूमि का नामान्तकरण स्वीकार किया गया जिसके अनुसार पुराने खसरा नम्बर 3834 में से 5-09-10 बीघा भूपेन्द्रसिंह व उसके पिता नरदेव सिंह के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया गया जो सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया तथा बाद खरीद रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 उक्त भूमि पर बतौर तन्हा खातेदार कृषक काबिज चला आ रहा है। रेस्पोंडेन्ट भूपेन्द्र के पिता नरदेव सिंह फौत हो चुके है, भूपेन्द्र सिंह ही उनका एक मात्र वारिस है। नामान्तकरण संख्या 127 की पालना में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं की गया इसलिए वाद दायर करने की आवश्यकता हुयी तथा अप्रार्थी/अपीलांत को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हुआ क्योंकि ¹ क्रयशुदा भूमि 05-09-10 को अन्यत्र हस्तांतरित करने बाबत कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं करे और ना ही राजस्व अभिलेखें में प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट के अलावा अन्य किसी का नाम दर्ज करें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये तथा दिनांक 06.05.2022 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड की यथारिथति बनायी रखी जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त

अजमेर अपील प्राधिकारी
अजमेर

02/07/22

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2022/225

चन्दन सिंह vs जसजस सिंह

2022/422

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
जाती हुए

श्री रोहित सोनी

श्री प्रजित सिंह

4A

आदेश अप्रार्थी/अपीलांट को किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न नहीं होती है फिर भी अप्रार्थी/अपीलांट ने माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है, जो अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जो चलने योग्य नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने से किसी प्रकार से क्षति नहीं हो रही है। वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजी को संरक्षित व सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है तो अप्रार्थी/अपीलांट विवादित आराजी को अन्यत्र रहन, बय व मुन्तकिल कर देगा तो अपूर्ण क्षति रेस्पोजेन्ट को ही होनी है इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा अपील पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी के रिजिस्टर्ड सह-खातेदारान कुलदीन सिंह, रवीन्द्रसिंह पुत्रान अरुणसिंह एवं मंजू कंवर पत्नि अरुण सिंह के नाम 267/390 हिस्सा सम्बन्ध 2073-76 जमाबंदी वर्ष 2019 में अंकित है, जिनसे कि अपीलांट ने दिनांक 20.04.2022 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया है। उक्त आराजी पर विक्रेतागण पूर्वजों के समय से अपने-अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक सह-खातेदार की हैसियत से काश्त कर रहे हैं, जिस क्रम में उन्होंने अपने अपने हिस्से अनुसार बाड़, फसल तारबंदी आदी की हुई है, चूंकि वादी व उसका परिवार अशांति प्रिय व्यक्ति होकर झगड़े फंसाद कर हैरान-परेशान करने की नियत रखते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2022 के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है, जिस पर अभिभाषक उभयपक्ष की दिनांक 11.01.2023 को सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2022 की क्रियान्विति, पालना व प्रभाव को आगामी पेशी तक स्थगित किया गया है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2022 को निरस्त किया जावे। अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 01 ने अपने जवाब बहस में कथन किया कि रेस्पोजेन्ट/प्राथी भूपेन्द्र सिंह व उनके पिता नरदेव सिंह ने पूर्व खातेदार छीतर पुत्र रामचन्द्र दसोगा से उक्त भूमि कुल 08-00-10 बीघा में से 05-09-10 बीघा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था इस खसरे की शेष भूमि 02-11-00 अन्य व्यक्ति ने खरीदी थी जैसा की नामान्तरण संख्या 127 दिनांक 13.09.1988 को रेस्पोजेन्ट संख्या 01 व उसके पिता के नाम उक्त क्रय शुदा-भूमि का नामान्तरण स्वीकार किया गया जिसके अनुसार पुराने खसरा नम्बर 3834 में से 5-09-10 बीघा भूपेन्द्रसिंह व उसके पिता नरदेव सिंह के नाम नामान्तरण स्वीकार किया गया जो सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया तथा बाद खरीद रेस्पोजेन्ट संख्या 01 उक्त भूमि पर बतौर तन्हा खातेदार कृषक काबिज चला आ रहा है। रेस्पोजेन्ट भूपेन्द्र के पिता नरदेव सिंह फौत हो चुके हैं, भूपेन्द्र सिंह ही उनका एक मात्र वारिस है। नामान्तरण संख्या 127 की पालना में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं की गया इसलिए वाद दायर करने की आवश्यकता हुयी। अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा में विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये हैं जो विधि सम्मत है। हमारे द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी बाबत अपीलांट एवं रेस्पोजेन्ट दोनो का कथन है कि विवादित आराजी उन्होंने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद की है, जिसका निस्तारण तो बाद वाद पत्र में साक्ष्य व सुनवाई के पश्चात् तय होना है तब तक विवादित आराजी को सुरक्षित व संरक्षित किया जाना चाहिए ऐसा उच्चतर न्यायालयों ने अपने अनेको आदेशों में यह प्रतिपादित किया हुआ है, इसलिए न्यायहित में अपील को इसी स्तर पर अपील को निर्णित की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 28/2020 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 को इस प्रकार संशोधित किया जाना


प्रजित सिंह

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

422/2022/2417A

20-6-2022 4/1-2022 24/3/148

तारीख

2022/422

दुबम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

पेशी

श्री रोहित सोनी

श्री

श्रीजी/1118-1

लगावती

उचित समझते है कि विवादित आराजी बाबत उभय पक्षकारान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत् बनाये रखें तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर जवाब प्राप्त कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए इस आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील को निर्णित की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 28/2020 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि विवादित आराजी बाबत उभय पक्षकारान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत् बनाये रखें तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर जवाब प्राप्त कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए इस आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.08.2023 को उपस्थित हों। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।


राजेश अपाल प्राधिकारी
अजमेर